



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

गाँव से विश्व तक: एकात्म मानव दर्शन के आधार पर पंचायत की भूमिका

रचना देवी

शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग,

गोकुल दास हिंदू गर्ल्स डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद (उ.प्र.)

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

प्रो. (डॉ.) मीनाक्षी शर्मा

विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग,

गोकुल दास हिंदू गर्ल्स डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद (उ.प्र.)

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

सारांश

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायतें स्थानीय स्वशासन की आधारशिला हैं, जो गाँव से लेकर राष्ट्र और विश्व तक विकास की प्रक्रिया को दिशा प्रदान करती हैं। इस संदर्भ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानव दर्शन पंचायतों की भूमिका को एक समग्र, मूल्य-आधारित और मानव-केंद्रित दृष्टि प्रदान करता है। एकात्म मानव दर्शन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और प्रकृति के पारस्परिक समन्वय पर आधारित है, जिसमें विकास को केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित न मानकर सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और पर्यावरणीय आयामों से जोड़ा गया है। पंचायतें इस दर्शन को व्यवहार में उतारने का सबसे प्रभावी माध्यम हैं, क्योंकि वे स्थानीय आवश्यकताओं, सहभागिता और सामुदायिक उत्तरदायित्व पर आधारित शासन को सशक्त बनाती हैं।

यह शोध-पत्र 'गाँव से विश्व तक' की अवधारणा के अंतर्गत एकात्म मानव दर्शन के आलोक में पंचायतों की भूमिका का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। शोध-पत्र में



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

यह स्पष्ट किया गया है कि पंचायतें ग्राम विकास, सामाजिक समरसता, महिला एवं वंचित वर्गों के सशक्तिकरण, तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। साथ ही, वैश्विक संदर्भ में पंचायतें सतत विकास लक्ष्यों (SDGs), पर्यावरण संरक्षण और सहभागी लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर साकार करने की क्षमता रखती हैं।

शोध-पत्र यह प्रतिपादित करता है कि जब पंचायतें एकात्म मानव दर्शन से प्रेरित होकर कार्य करती हैं, तब स्थानीय विकास वैश्विक मानव-कल्याण से जुड़ जाता है। निष्कर्षतः, पंचायतों का सशक्तिकरण केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि 'लोकल टू ग्लोबल' दृष्टि के माध्यम से संतुलित, समावेशी और सतत विकास का आधार है। इस प्रकार, एकात्म मानव दर्शन के आधार पर पंचायतें गाँव से विश्व तक मानव-केंद्रित विकास की सेतु बन सकती हैं।

मुख्य शब्द: एकात्म मानव दर्शन, पंचायत, ग्राम स्वशासन, गाँव से विश्व, स्थानीय से वैश्विक विकास, सतत विकास

भूमिका:

भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में ग्राम केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की आधारशिला रहा है। वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में जब विकास की अवधारणा 'स्थानीय से वैश्विक' (Local to Global) की ओर अग्रसर है, तब "गाँव से विश्व" की अवधारणा विशेष प्रासंगिक हो जाती है। यह विचार इस तथ्य को रेखांकित करता है कि यदि विकास की जड़ें गाँव में सुदृढ़ हों, तो उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से राष्ट्र और विश्व स्तर तक पहुँचता है। इसी संदर्भ में पंचायतें लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की ऐसी संस्थाएँ हैं, जो स्थानीय आवश्यकताओं, सहभागिता और आत्मनिर्भरता के माध्यम से समग्र



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

विकास को दिशा देती हैं। शोध-पत्र की प्रासंगिकता इस बात में निहित है कि आज भी भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और राष्ट्रीय विकास की सफलता ग्राम-स्तरीय संस्थाओं की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है।ⁱ

‘गाँव से विश्व’ की अवधारणा का अर्थ यह है कि विकास केवल ऊपर से नीचे (Top-down) थोपे गए मॉडलों से नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर (Bottom-up) उभरने वाली प्रक्रियाओं से स्थायी और समावेशी बनता है। ग्राम स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ कर ही वैश्विक मानव-कल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यह दृष्टि वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों से भी मेल खाती है, जहाँ स्थानीय समुदायों की भूमिका को केंद्रीय माना गया है।ⁱⁱ

इस वैचारिक पृष्ठभूमि में एकात्म मानव दर्शन का महत्व विशेष रूप से उभरता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित यह दर्शन मानव जीवन को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक—चारों आयामों में समग्र रूप से देखने पर बल देता है। यह दर्शन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और प्रकृति के बीच संतुलन और समन्वय को विकास का मूल आधार मानता है। पंचायतें इस दर्शन को व्यवहार में उतारने का सबसे उपयुक्त मंच हैं, क्योंकि वे स्थानीय समाज की नैतिकता, कर्तव्यबोध और सहभागिता पर आधारित शासन को सशक्त करती हैं।ⁱⁱⁱ

भारतीय लोकतंत्र में पंचायतों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे न केवल प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण का माध्यम हैं, बल्कि सहभागी लोकतंत्र की प्रयोगशाला भी हैं। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देकर उन्हें लोकतंत्र की तीसरी परत के रूप में स्थापित किया। इससे स्थानीय स्तर पर निर्णय-



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

निर्माण, सामाजिक न्याय और विकास की प्रक्रियाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित हुई।^{iv}

इस शोध-पत्र का उद्देश्य एकात्म मानव दर्शन के आलोक में पंचायतों की भूमिका का विश्लेषण करना है—विशेषकर 'गाँव से विश्व' की विकास-दृष्टि के संदर्भ में। शोध प्रश्न यह हैं: क्या पंचायतें समग्र मानव विकास की इकाई बन सकती हैं? एकात्म मानव दर्शन पंचायतों को कैसे वैचारिक आधार प्रदान करता है? शोध-पत्र की सीमा यह है कि यह मुख्यतः सैद्धांतिक एवं द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, न कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर। फिर भी, यह शोध पंचायतों की वैचारिक और लोकतांत्रिक भूमिका को समझने में सहायक सिद्ध होता है।

एकात्म मानव दर्शन: वैचारिक पृष्ठभूमि:

एकात्म मानव दर्शन भारतीय राजनीतिक-सामाजिक चिंतन की एक मौलिक देन है, जो मानव जीवन को खंडित न मानकर समग्र रूप में समझने पर बल देता है। इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि भारतीय दर्शन—विशेषकर उपनिषद, गीता और धर्म-सूत्रों—में निहित है, जहाँ मानव, समाज और प्रकृति के बीच सहअस्तित्व और संतुलन को जीवन का मूल सिद्धांत माना गया है। उपाध्याय के अनुसार, आधुनिक विकास मॉडल मानव को केवल आर्थिक इकाई के रूप में देखते हैं, जिससे सामाजिक असमानता और नैतिक पतन उत्पन्न होता है।^v

इस दर्शन में व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और प्रकृति के बीच अविभाज्य संबंध को स्वीकार किया गया है। व्यक्ति समाज से अलग नहीं है, समाज राष्ट्र की जीवंत अभिव्यक्ति है और राष्ट्र प्रकृति के साथ सहजीवी संबंध में स्थित है। यदि विकास की प्रक्रिया में इन तत्वों के बीच संतुलन टूटता है, तो संकट अनिवार्य हो जाता



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

है। इसलिए एकात्म मानव दर्शन अधिकारों के साथ कर्तव्यों और स्वतंत्रता के साथ अनुशासन को समान महत्व देता है।^{vi}

भारतीय दर्शन में समग्र मानव विकास की अवधारणा सदैव से विद्यमान रही है। 'पुरुषार्थ'—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—मानव जीवन के संतुलित विकास का प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं। यह अवधारणा भौतिक उन्नति के साथ नैतिकता और आध्यात्मिकता को भी विकास का अंग मानती है। एकात्म मानव दर्शन इसी परंपरा का आधुनिक रूपांतरण है, जो नीति और शासन को नैतिक आधार प्रदान करता है।^{vii}

एकात्म मानव दर्शन और विकेन्द्रीकरण के बीच गहरा संबंध है। उपाध्याय का मानना था कि केंद्रीकृत शासन मानव की स्वायत्तता और रचनात्मकता को सीमित करता है। इसके विपरीत, विकेन्द्रीकरण स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय-निर्माण को संभव बनाता है और समुदाय की सहभागिता को सुदृढ़ करता है। पंचायतें इस विकेन्द्रीकृत व्यवस्था का व्यावहारिक रूप हैं, जहाँ एकात्म मानव दर्शन की समन्वयात्मक सोच को मूर्त रूप दिया जा सकता है।^{viii}

पंचायत व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास:

पंचायत व्यवस्था की जड़ें प्राचीन भारत में गहराई तक फैली हुई हैं। वैदिक और उत्तर-वैदिक काल में सभा और समिति जैसी संस्थाएँ ग्राम-स्तरीय निर्णय-निर्माण के केंद्र थीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम प्रशासन, ग्रामिक और स्थानीय स्वशासन के विस्तृत उल्लेख मिलते हैं। उस काल में ग्राम अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर इकाई था, जहाँ सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक कार्य स्थानीय स्तर पर संपन्न होते थे।^{ix}



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

औपनिवेशिक काल में पंचायतों की स्थिति कमजोर हो गई। ब्रिटिश प्रशासन ने केंद्रीकृत शासन प्रणाली को प्राथमिकता दी, जिससे पारंपरिक ग्राम स्वशासन संस्थाएँ हाशिए पर चली गईं। यद्यपि 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की वकालत की, फिर भी पंचायतें वास्तविक शक्ति से वंचित रहीं।^x

स्वतंत्रता के पश्चात पंचायत व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रयास हुए। बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति ने पंचायतों को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का आधार बनाने की सिफारिश की। अंततः 73वें संविधान संशोधन (1992) ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और उन्हें विकास, सामाजिक न्याय तथा सहभागी लोकतंत्र की प्रमुख संस्था के रूप में स्थापित किया।^{xi}

इस प्रकार, ऐतिहासिक विकासक्रम में पंचायतें 'गाँव से विश्व' की विकास-दृष्टि को साकार करने की सशक्त संस्थाएँ बनकर उभरती हैं, विशेषकर जब उन्हें एकात्म मानव दर्शन का वैचारिक आधार प्राप्त हो।

पंचायत और एकात्म मानव दर्शन का अंतर्संबंध:

पंचायत और एकात्म मानव दर्शन के बीच का संबंध भारतीय स्वशासन की आत्मा को अभिव्यक्त करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानव दर्शन में स्वशासन (Self-Governance) को मानव विकास की मूल शर्त माना गया है। इस दृष्टि से पंचायत केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि व्यक्ति, परिवार और समुदाय के समन्वित विकास की मूल संस्था है। उपाध्याय के अनुसार जब निर्णय-प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर होती है, तब शासन मानवीय, उत्तरदायी और नैतिक बनता है। पंचायतें इस दर्शन को व्यवहार में उतारते हुए लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर सशक्त करती हैं।^{xii}



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

पंचायत को स्वशासन की मूल इकाई के रूप में देखने का अर्थ यह है कि ग्राम अपने विकास का स्वयं नियंत्रण बने। एकात्म मानव दर्शन केंद्रीकरण के स्थान पर विकेन्द्रीकरण का समर्थन करता है, क्योंकि स्थानीय समाज अपनी आवश्यकताओं, संसाधनों और प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझता है। पंचायतों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित निर्णय-प्रक्रिया—जैसे जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका—एकात्म मानव दर्शन के उस सिद्धांत से मेल खाती है, जिसमें व्यक्ति और समाज को विकास की केंद्रीय इकाई माना गया है।^{xiii}

एकात्म मानव दर्शन अधिकारों के साथ कर्तव्यों के संतुलन पर विशेष बल देता है। आधुनिक लोकतंत्र में अधिकारों की चर्चा तो व्यापक है, किंतु कर्तव्यों की उपेक्षा सामाजिक असंतुलन को जन्म देती है। पंचायत व्यवस्था इस संतुलन को व्यवहार में लाने का मंच है, जहाँ नागरिक अधिकारों के साथ समुदाय, पर्यावरण और भावी पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व भी निभाते हैं। ग्राम सभा की सहभागिता, सामूहिक श्रम और सामाजिक उत्तरदायित्व—ये सभी कर्तव्य-आधारित शासन के उदाहरण हैं।^{xiv}

समुदाय-केंद्रित शासन और सामाजिक समरसता एकात्म मानव दर्शन का केंद्रीय तत्व है। पंचायतें जाति, वर्ग और लिंग के पार समुदाय को एक साझा मंच प्रदान करती हैं। स्थानीय विवादों का संवाद के माध्यम से समाधान, सामूहिक निर्णय और सांस्कृतिक गतिविधियाँ सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करती हैं। इस प्रकार पंचायतें एकात्म मानव दर्शन के उस लक्ष्य को साकार करती हैं, जिसमें समाज को सहयोग, कर्तव्य और नैतिकता से जोड़ा गया है।^{xv}



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

ग्राम विकास में पंचायत की भूमिका:

ग्राम विकास में पंचायत की भूमिका बहुआयामी और निर्णायक है। ग्राम योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन पंचायतों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्राम पंचायतों को स्थानीय विकास योजनाएँ बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार मिला, जिससे विकास की प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर अग्रसर हुई। ग्राम सभा के माध्यम से समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित होती है, जो एकात्म मानव दर्शन के सहभागी विकास सिद्धांत से मेल खाती है।^{xvi}

शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में पंचायतों का योगदान मानव विकास की आधारशिला को मजबूत करता है। प्राथमिक विद्यालयों की निगरानी, आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन, टीकाकरण और स्वच्छता अभियानों में पंचायतों की सक्रिय भूमिका देखी जाती है। ये प्रयास केवल भौतिक विकास नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास को भी प्रोत्साहित करते हैं, जो एकात्म मानव दर्शन की समग्र दृष्टि का अनिवार्य अंग है।^{xvii}

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका सृजन में पंचायतों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मनरेगा, स्व-सहायता समूह, कुटीर एवं लघु उद्योग, कृषि एवं पशुपालन—इन सभी क्षेत्रों में पंचायतें स्थानीय संसाधनों के उपयोग से रोजगार सृजन को बढ़ावा देती हैं। यह स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की उसी अवधारणा का व्यावहारिक रूप है, जिसे एकात्म मानव दर्शन प्रतिपादित करता है।^{xviii}

महिला एवं वंचित वर्गों का सशक्तिकरण पंचायत व्यवस्था की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आरक्षण के माध्यम से महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की भागीदारी ने न केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाया, बल्कि सामाजिक आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को भी सुदृढ़ किया। यह समावेशी



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

विकास एकात्म मानव दर्शन के उस सिद्धांत को मूर्त रूप देता है, जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान को विकास का मानदंड माना गया है।^{xix}

सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में पंचायत:

सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पंचायतों की भूमिका एकात्म मानव दर्शन के साथ गहरे रूप से जुड़ी हुई है। यह दर्शन मनुष्य और प्रकृति के सहजीवी संबंध को स्वीकार करता है और प्रकृति के शोषण के स्थान पर संरक्षण पर बल देता है। पंचायतें प्राकृतिक संसाधनों—जल, वन और भूमि—के संरक्षण एवं प्रबंधन में स्थानीय ज्ञान और सामुदायिक सहभागिता का उपयोग करती हैं।^{xx}

जल संरक्षण में पंचायतों की भूमिका—जैसे तालाबों का पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और जल-साक्षरता—स्थानीय स्तर पर जल संकट के समाधान में सहायक सिद्ध होती है। इसी प्रकार वन पंचायतें, सामुदायिक वानिकी और भूमि संरक्षण कार्यक्रम पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में योगदान देते हैं। ये प्रयास एकात्म मानव दर्शन की उस सोच को साकार करते हैं, जिसमें प्रकृति को उपभोग की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन-सहचरी माना गया है।^{xxi}

एकात्म मानव दर्शन और प्रकृति-संरक्षण का संबंध नैतिकता से भी जुड़ा है। उपाध्याय के अनुसार प्रकृति के प्रति कर्तव्यबोध के बिना विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। पंचायतें इस कर्तव्यबोध को स्थानीय परंपराओं, उत्सवों और सामूहिक नियमों के माध्यम से सुदृढ़ करती हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण सामाजिक आचरण का हिस्सा बनता है, न कि केवल सरकारी नीति।^{xxii}

स्थानीय स्तर पर जलवायु जागरूकता बढ़ाने में पंचायतों की भूमिका दिन-प्रतिदिन महत्वपूर्ण होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव—सूखा, बाढ़, तापमान वृद्धि—का सामना सबसे पहले गाँवों को करना पड़ता है। पंचायतें



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

स्थानीय अनुकूलन रणनीतियाँ विकसित कर समुदाय को जागरूक और सक्षम बनाती हैं। इस प्रकार, पंचायतें एकात्म मानव दर्शन के आलोक में सतत, संतुलित और मानव-केंद्रित विकास की वाहक बनती हैं।

समग्र रूप से, पंचायत, ग्राम विकास और पर्यावरण संरक्षण—तीनों मिलकर 'गाँव से विश्व' की उस विकास-दृष्टि को साकार करते हैं, जिसमें स्थानीय स्वशासन वैश्विक मानव-कल्याण की नींव बनता है।

'गाँव से विश्व' की यात्रा में पंचायत की भूमिका:

'गाँव से विश्व' की यात्रा का मूल अभिप्राय यह है कि स्थानीय स्तर पर सुदृढ़ और सहभागी विकास ही वैश्विक मानव-कल्याण की स्थायी नींव रख सकता है। पंचायतें इस यात्रा की केंद्रीय कड़ी हैं, क्योंकि वे स्थानीय आवश्यकताओं, संसाधनों और आकांक्षाओं को विकास-प्रक्रिया से जोड़ती हैं। स्थानीय से वैश्विक सोच का विकास तब संभव होता है, जब ग्राम स्तर पर निर्णय-निर्माण, योजना और क्रियान्वयन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। पंचायतें स्थानीय समस्याओं—जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और पर्यावरण—के समाधान खोजते हुए वैश्विक चुनौतियों के प्रति भी जागरूकता पैदा करती हैं। यह दृष्टि नीचे से ऊपर (Bottom-up) विकास की उस अवधारणा को पुष्ट करती है, जिसमें स्थानीय सफलताएँ वैश्विक स्तर पर अनुकरणीय बनती हैं।^{xxiii}

वैश्विक विकास लक्ष्यों (SDGs) और पंचायतों के बीच गहरा अंतर्संबंध है। गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल, स्वच्छता और जलवायु कार्रवाई—ये सभी लक्ष्य स्थानीय स्तर पर ही साकार होते हैं। पंचायतें ग्राम योजनाओं के माध्यम से इन लक्ष्यों को जमीनी स्तर पर लागू करती हैं और



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

समुदाय को सहभागी बनाती हैं। इस प्रकार, SDGs किसी दूरस्थ वैश्विक एजेंडा के बजाय ग्राम-जीवन का हिस्सा बन जाते हैं।^{xxiv}

ग्रामीण नवाचार और वैश्विक सहभागिता पंचायतों की एक उभरती हुई भूमिका है। स्थानीय तकनीकी नवाचार, स्व-सहायता समूहों की पहल, कृषि और जल प्रबंधन के स्थानीय समाधान वैश्विक मंचों पर सराहे जा रहे हैं। पंचायतें इन नवाचारों को संस्थागत समर्थन देकर 'ज्ञान-साझेदारी' (Knowledge Sharing) को बढ़ावा देती हैं। यह प्रक्रिया 'लोकल टू ग्लोबल' मॉडल को सशक्त बनाती है, जहाँ स्थानीय अनुभव वैश्विक नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावित करते हैं।^{xxv}

'लोकल टू ग्लोबल' मॉडल पंचायतों को केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि वैश्विक नागरिकता के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित करता है। जब ग्राम सभा में पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागिता विकसित होती है, तो वही मूल्य वैश्विक लोकतांत्रिक संस्कृति को भी सुदृढ़ करते हैं। इस प्रकार, पंचायतें 'गाँव से विश्व' की यात्रा में विकास, लोकतंत्र और मानव-कल्याण की सेतु बनती हैं।

पंचायत, लोकतंत्र और सामाजिक समरसता:

पंचायतें सहभागी लोकतंत्र की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति हैं। वे नागरिकों को केवल मतदाता नहीं, बल्कि निर्णय-निर्माता के रूप में सक्रिय भूमिका प्रदान करती हैं। ग्राम सभा के माध्यम से जनता सीधे विकास योजनाओं, संसाधन आवंटन और सामाजिक मुद्दों पर संवाद करती है। यह सहभागिता लोकतंत्र को औपचारिक प्रक्रिया से आगे बढ़ाकर जीवन-पद्धति बनाती है।^{xxvi}

सामाजिक न्याय, समानता और समावेशन के संदर्भ में पंचायतों की भूमिका ऐतिहासिक है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण ने सत्ता-संरचना में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

इससे न केवल प्रतिनिधित्व बढ़ा, बल्कि सामाजिक आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का भी विकास हुआ। पंचायतें कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से हाशिए के समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ती हैं।^{xxvii}

जाति, वर्ग और लिंग-आधारित असमानताओं के समाधान में पंचायतें संवाद और सहभागिता का मंच प्रदान करती हैं। स्थानीय विवादों का सामुदायिक समाधान, पारदर्शी निर्णय-प्रक्रिया और समान अवसरों का सृजन सामाजिक विभाजनों को कम करने में सहायक होता है। पंचायतों की यह भूमिका सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करती है, जो भारतीय समाज की बहुलतावादी संरचना के लिए अनिवार्य है।^{xxviii}

सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में पंचायतें स्थानीय परंपराओं, उत्सवों और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से साझा पहचान को मजबूत करती हैं। संस्कृति, भाषा और लोकाचार के प्रति सम्मान राष्ट्रीय एकता की जड़ें गहरी करता है। जब स्थानीय सांस्कृतिक चेतना लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्रीय एकता केवल संवैधानिक आदर्श न रहकर सामाजिक यथार्थ बन जाती है।^{xxix}

समग्रतः, पंचायतें 'गाँव से विश्व' की यात्रा में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक एकता को एकीकृत करती हैं। वे स्थानीय स्वशासन को वैश्विक मानव-कल्याण से जोड़ते हुए एकात्म मानव दर्शन की उस समन्वयात्मक दृष्टि को साकार करती हैं, जिसमें विकास मानव, समाज और प्रकृति—तीनों के हित में संतुलित रूप से आगे बढ़ता है।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

निष्कर्ष:

एकात्म मानव दर्शन के आलोक में पंचायत की भूमिका का समेकित मूल्यांकन यह स्पष्ट करता है कि पंचायतें केवल प्रशासनिक संस्थाएँ नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा और समग्र मानव विकास की आधारशिला हैं। एकात्म मानव दर्शन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और प्रकृति के बीच संतुलन एवं समन्वय को विकास का मूल सिद्धांत मानता है, और पंचायतें इस दर्शन को व्यवहारिक रूप देने का सबसे सशक्त माध्यम हैं। स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित निर्णय-प्रक्रिया, अधिकारों के साथ कर्तव्यों का संतुलन, तथा समुदाय-केंद्रित शासन पंचायतों को मानव-केंद्रित और नैतिक बनाता है। इससे विकास केवल भौतिक प्रगति तक सीमित न रहकर सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय आयामों को भी समाहित करता है।

पंचायतों के माध्यम से ग्राम विकास, सामाजिक न्याय, महिला एवं वंचित वर्गों का सशक्तिकरण तथा प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन संभव होता है। सहभागी लोकतंत्र की प्रयोगशाला के रूप में पंचायतें नागरिकों को निर्णय-निर्माण में सक्रिय भूमिका प्रदान करती हैं, जिससे लोकतांत्रिक चेतना गहरी होती है। एकात्म मानव दर्शन की समरसतामूलक दृष्टि जाति, वर्ग और लिंग आधारित विभाजनों को कम करने में सहायक सिद्ध होती है और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देती है। इस प्रकार पंचायतें स्थानीय स्वशासन को नैतिकता, कर्तव्यबोध और सांस्कृतिक चेतना से जोड़ती हैं।

स्थानीय स्वशासन से वैश्विक मानव-कल्याण तक की संभावनाएँ तब साकार होती हैं, जब पंचायतें 'लोकल टू ग्लोबल' दृष्टि अपनाती हैं। सतत विकास लक्ष्यों, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु जागरूकता जैसे वैश्विक मुद्दे पंचायतों के माध्यम



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

से जमीनी स्तर पर लागू किए जा सकते हैं। स्थानीय नवाचार और सामुदायिक सहभागिता वैश्विक विकास विमर्श को व्यावहारिक आधार प्रदान करती है। अंततः यह कहा जा सकता है कि एकात्म मानव दर्शन के मार्गदर्शन में सशक्त पंचायतें गाँव से विश्व तक मानव-केंद्रित, समावेशी और सतत विकास की सेतु बन सकती हैं, जहाँ स्थानीय स्वशासन वैश्विक शांति, समरसता और मानव-कल्याण की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाता है।

सन्दर्भ

- i. कोठारी, रजनी, पॉलिटिक्स इन इंडिया, ओरिएंट लॉन्गमैन, नई दिल्ली, 1970, पृ. 214
- ii. सेन, अमर्त्य, डेवलपमेंट ऐज़ फ्रीडम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1999, पृ. 153
- iii. उपाध्याय, पंडित दीनदयाल, एकात्म मानववाद, दीनदयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली, 1989, पृ. 22
- iv. भारत सरकार, भारतीय संविधान, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली
- v. उपाध्याय, पंडित दीनदयाल, एकात्म मानववाद, दीनदयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली, 1989, पृ. 17
- vi. उपाध्याय, पंडित दीनदयाल, धर्म और राजनीति, दीनदयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली, 1990, पृ. 39
- vii. राधाकृष्णन, सर्वपल्ली, इंडियन फिलॉसफी, जॉर्ज एलन एंड अनविन, लंदन, 1951, पृ. 112
- viii. उपाध्याय, पंडित दीनदयाल, ग्राम स्वराज और विकास, दीनदयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली, 1990, पृ. 46
- ix. कौटिल्य, अर्थशास्त्र, चौखंबा प्रकाशन, वाराणसी, 1960, पृ. 78



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

-
- x. चटर्जी, पी.एन., लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, 1972, पृ. 64
- xi. भारत सरकार, पंचायती राज अधिनियम, नई दिल्ली
- xii. उपाध्याय, पंडित दीनदयाल, एकात्म मानववाद, दीनदयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली, 1989, पृ. 35
- xiii. उपाध्याय, पंडित दीनदयाल, ग्राम स्वराज और विकास, दीनदयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली, 1990, पृ. 41
- xiv. शर्मा, बी.एल., भारतीय पंचायती राज व्यवस्था, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 2014, पृ. 96
- xv. उपाध्याय, पंडित दीनदयाल, सामाजिक समरसता, दीनदयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली, 1991, पृ. 28
- xvi. भारत सरकार, पंचायती राज अधिनियम, नई दिल्ली, 1992
- xvii. सेन, अमर्त्य, डेवलपमेंट ऐज़ फ्रीडम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1999, पृ. 142
- xviii. उपाध्याय, पंडित दीनदयाल, स्वदेशी और राष्ट्रनिर्माण, भारतीय जनसंघ प्रकाशन, नई दिल्ली, 1966, पृ. 33
- xix. अग्रवाल, बीना, जेंडर एंड गवर्नेंस, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2010, पृ. 119
- xx. उपाध्याय, पंडित दीनदयाल, एकात्म मानववाद, दीनदयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली, 1989, पृ. 61
- xxi. राधाकृष्णन, सर्वपल्ली, इंडियन फिलॉसफी, जॉर्ज एलन एंड अनविन, लंदन, 1951, पृ. 205
- xxii. उपाध्याय, पंडित दीनदयाल, धर्म और राजनीति, दीनदयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली, 1990, पृ. 52
- xxiii. सेन, अमर्त्य, डेवलपमेंट ऐज़ फ्रीडम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1999, पृ. 176



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

-
- xxiv. संयुक्त राष्ट्र, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड: 2030 एजेंडा, न्यूयॉर्क, 2015
- xxv. शर्मा, बी.एल., ग्रामीण विकास और स्थानीय नवाचार, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2016, पृ. 92
- xxvi. कोठारी, रजनी, पॉलिटिक्स इन इंडिया, ओरिएंट लॉन्गमैन, नई दिल्ली, 1970, पृ. 221
- xxvii. अग्रवाल, बीना, जेंडर एंड गवर्नेंस, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2010, पृ. 137
- xxviii. उपाध्याय, पंडित दीनदयाल, सामाजिक समरसता, दीनदयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली, 1991, पृ. 41
- xxix. उपाध्याय, पंडित दीनदयाल, संस्कृति और राष्ट्र, भारतीय जनसंघ प्रकाशन, नई दिल्ली, 1966, पृ. 58